एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस :
निर्यात लाभ

सितम्बर 2016
खंड XXXII अंक III

इस अंक में

1-3 भारतीय फार्मा उद्योग : चुनौतियां और संभावनाएं
4 कैरिकॉम के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंध
5 आसियान के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंध
6 ईरान के साथ व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं
7 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
8 तिमाही गतिविधियां
9 मशीनरी सेक्टर : हालिया ट्रेंड और संभावनाएं
10 भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का परिदृश्य
11 एक्ज़िम बैंक की गतिविधियां और साहित्य समीक्षा
12 देशों का सूक्ष्मावलोकन
13 मुद्रा जगत
14 माइग्रेशन और भारत में रेमिटैंस
15 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य
16 व्यापार एवं भागीदारी अवसर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

भारतीय फार्मा उद्योग : चुनौतियां और संभावनाएं

वैश्विक परिदृश्य

उभरते बाजारों में भारी मांग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति के चलते फार्मासूटिकल उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। वर्ष 2014 के दौरान वैश्विक रूप से फार्मासूटिकल बाजार 1027.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा था। वैश्विक फार्मासूटिकल उद्योग में उत्तर अमेरिका (मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका), यूरोप और जापान प्रमुख बाजार हैं। वर्ष 2014 में उत्तर अमेरिकी बाजार सबसे बड़ा बाजार बना रहा और कुल फार्मासूटिकल बिक्री का एक तिहाई से अधिक हिस्सा इसी बाजार में रहा। वर्ष 2014 के दौरान यूरोप में फार्मासूटिकल बिक्री कुल वैश्विक बिक्री की लगभग 22.3 प्रतिशत रही। वर्ष 2014 के दौरान एशियाई, अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में फार्मासूटिकल्स की बिक्री में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और संयुक्त रूप से यह क्षेत्र वैश्विक फार्मासूटिकल बाजार का लगभग 19.4 फीसदी रहा। वैश्विक फार्मासूटिकल बाजार में जापान और लैटिन अमेरिका का हिस्सा क्रमशः 7.9 प्रतिशत और 7 प्रतिशत रहा।

2010 से 2014 के दौरान फार्मासूटिकल उत्पादों (एच एस कोड 30) का वैश्विक निर्यात 443.2 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 510.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया और इसमें 3.6 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014 के दौरान जर्मनी फार्मासूटिकल उत्पादों का अग्रणी निर्यातक रहा (वैश्विक निर्यात में 15.6 प्रतिशत हिस्से के साथ)। इसके बाद स्विट्जरलैंड (12.3 प्रतिशत), बेल्जियम (9.8 प्रतिशत) और संयुक्त राज्य अमेरिका (8.6 प्रतिशत) का स्थान रहा। वृद्धि के लिहाज से देखें तो 2010 से 2014 के दौरान भारत से निर्यात में सबसे ज्यादा 17.6 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद इटली, और डेनमार्क का स्थान रहा जहां क्रमशः 11.5 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि दर्ज की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में सबसे बड़ा आयातक रहा, जिसने फार्मासूटिकल उत्पादों के वैश्विक आयात का 13.8 प्रतिशत अकेले ही आयात किया।

भारतीय परिदृश्य

उद्योग अनुमानों के अनुसार, दुनिया भर में, भारतीय फार्मासूटिकल बाजार मात्रा के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के लिहाज से तेरहवां सबसे बड़ा बाजार है। वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापार में मंदी के बावजूद फार्मासूटिकल उत्पादों के निर्यात में मध्यम वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 के दौरान थोक दवाओं का निर्यात 3.6 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और इस अवधि के दौरान इन निर्यातों में लगभग 0.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। दवा फॉर्म्यूलेशन का निर्यात 12.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से बढ़ा और 2015-16 के दौरान 12.8 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान दवा फॉर्म्यूलेशन के लिए प्रमुख निर्यात स्थलों में संयुक्त राज्य अमेरिका (39.5 प्रतिशत हिस्से के साथ) का सर्वोच्च स्थान रहा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका (4.1 प्रतिशत), ब्रिटेन (3.6 प्रतिशत), नाइजीरिया (3.0 प्रतिशत) और रूस (2.7 फीसदी) का स्थान रहा।

संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से थोक दवाओं का अग्रणी आयातक है और 2015-16 के दौरान भारत से कुल निर्यात में उसकी हिस्सेदारी लगभग 11.2 प्रतिशत रही। भारत से थोक दवाओं के अन्य महत्वपूर्ण आयातकों में जर्मनी (4.2 प्रतिशत), तुर्की (3.4 प्रतिशत), ईरान (3.3 प्रतिशत), ब्राजील (3.2 प्रतिशत) और मिस्र (3.2 प्रतिशत) शामिल हैं।

चुनौतियां और संभावनाएं

प्रमुख बाहरी चुनौतियां

व्यापार समझौते

ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप करार (टीपीपी) और ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एडं इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (टीटीआईपी) का भारतीय फार्मा उद्योग पर गंभीर असर पड़ सकता है। फार्मा उद्योग पर टीपीपी के सामूहिक असर की बात की जाए तो इससे नवीन आविष्कार करने वाली कंपनियों को कम से कम 10 साल का अतिरिक्त एकाधिकार मिल जाएगा, जिससे उन कंपनियों पर नई दवाओं पर शोध का दबाव कम होने का पूर्वानुमान है। टीटीआईपी भारतीय फार्मा कंपनियों को उसी उत्पाद को बाजार में लाने से रोक सकता है, जो वे इस करार पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य देशों को लंबे समय से देती आ रही हैं। इन समझौतों का भारतीय जेनरिक उद्योग पर भी बड़ा प्रभाव पड़ने के आसार हैं। उद्योग सूत्रों के अनुसार 2017 के अंत से जेनरिक उद्योग में गिरावट शुरू हो सकती है और इन मेगा व्यापार सौदों का बड़ा असर 2020 तक दिखाई देने की संभावना है।

पीआईसीएस और ईयू-ट्रेडमार्क

पीआईसी/एस यानी फार्मासूटिकल इंस्पेक्शन को-ऑपरेशन स्कीम की नियामक अपेक्षाएं भारतीय फार्मा उद्योग के लिए प्रमुख चुनौती बन सकती हैं, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) फार्मा खंड के लिए, जिन्हें अपनी इकाइयों को पीआईसीएस के हार्मोनाइज्ड जीएमपी फ्रेमवर्क के समतुल्य बनाने के लिए उन्नत करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें भारी निवेश की जरूरत होगी। एक तरफ सदस्यता लेना चुनौतीपूर्ण है तो दूसरी तरफ यह भी आशंका है कि पीआईसीएस का हिस्सा न बनना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि इससे पीआईसीएस सदस्य देशों के बढ़ते बाजार को खोने का डर है। यूरोपीय संघ (ईयू) का नया ट्रेडमार्क कानून, न केवल ईयू में रजिस्टर्ड कानूनों के समान ही सख्त है जो ट्रांजिट के दौरान माल पर सख्त प्रवर्तन उपाय लागू करता है, बल्कि ऐसे पारेषणों (कैंसाइन्मेंट) को ईयू बंदरगाहों और हवाईअड्डों पर ही सीज करने का अधिकार भी देता है, फिर भले ही वे किसी तीसरे देश के लिए ही क्यों न हों।

प्रमुख आंतरिक चुनौतियां

पुख्ता डाटा

कुशल श्रमशक्ति का अभाव भारत में फार्मा उद्योग के विकास में एक प्रमुख बाधा के रूप में उभरा है। संघीय और राज्य, दोनों स्तरों पर निरीक्षकों सहित संयुक्त नियामक स्टाफ की संख्या वर्तमान में लगभग 1500 है, जो भारत में 10,000 से अधिक दवा विनिर्माण सुविधाओं को देखते हुए काफी कम है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 3000 फार्मा विनिर्माण सुविधाओं के लिए 15,000 का नियामक स्टाफ है।

नैदानिक परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) डाटा की विश्वसनीयता

देश में किए गए नैदानिक परीक्षणों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि, नैदानिक परीक्षणों को विनियमित करने के लिए क्षमता उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी। इससे मरीजों पर विपरीत असर पड़ने पर सीमित हर्जाना, नैदानिक परीक्षणों के बिना दवाओं को मंजूरी और सहमति प्रक्रिया में चूक जैसे कुछ अनैतिक व्यवहार सामने आए हैं। हालांकि भारत सरकार ने विनियामक नियंत्रण उपाय बढ़ाए हैं, लेकिन नई नियामक नियंत्रण व्यवस्था के चलते नई दवाओं को मंजूरी मिलने में होने वाली देरी के कारण कुछ बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियों को भारत में अपनी नैदानिक परीक्षण गतिविधियों पर पुनर्विचार करना पड़ा है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

फार्मा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) दुनिया भर में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। अनिवार्य लाइसेंस (सीएल) देने से राजस्व नुकसान होता है। पेटेंट नियंत्रक द्वारा भारत में हाल ही में आए एक आदेश में यह व्यवस्था दी गई कि अनिवार्य लाइसेंस देना अंतिम उपाय होना चाहिए। पहले स्वैच्छिक लाइसेंस प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

थोक दवाओं और एपीआई के लिए चीन पर अति निर्भरता

भारतीय फार्मा उद्योग मेटफॉर्मिन, दर्दनाशक (एनालजेसिक) पैरासिटामोल, रैंटेडिन, विटामिन सी के लिए भारी मात्रा में चीन से आयात करता है। भारत पेनिसिलिन, सेफालोसफॉरिन और मैक्रोलाइड जैसे लगभग सभी एपीआई के लिए काफी हद तक चीन पर ही निर्भर है। महत्वपूर्ण दवाओं और एपीआई के लिए चीन पर अतिनिर्भरता की यह स्थिति भारतीय फार्मा उद्योग के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि चीन की नीतियों या दोनों देशों के बीच आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितियों में यदि कोई भी महत्त्वपूर्ण बदलाव होता है तो यह भारतीय फॉर्म्यूलेशन उद्योग के लिए बड़ा झटका होगा।

शोध एवं विकास (आर एंड डी)

अग्रणी भारतीय फार्मा कंपनियों की आगामी नई दवाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि नई पेटेंट व्यवस्था उद्योग के प्रमुख कारक बनने में सक्षम नहीं है। ऐसी शिकायतें भी हैं कि भारतीय कंपनियों की आर एंड डी गतिविधियां वैश्विक प्रकृति की जीवन शैली जनित रोगों पर केंद्रित हो रही हैं और वे टीबी और मलेरिया जैसी स्थानीय बीमारियों की दवा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट शोध में भारतीय कंपनियां भागीदार तो होती हैं, लेकिन उन्हें अधीनस्थ का दर्जा दिया जाता है, जो छोटी-मोटी परियोजनाओं के लिए ही शोध करती हैं। उन्हें नई दवा विकास की पूरी प्रक्रिया से परिचित नहीं कराया जाता है। भारतीय कंपनियों की यह अधीनस्थ स्थिति लंबे समय तक जारी रहने का दुष्परिणाम यह हो सकता है कि भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो सकती हैं।

आगे की राह

व्यापार समझौते और बाजार पहुंच

भारत टीपीपी में शामिल होने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, भारत अपनी व्यापार बाधा चिंताओं को ध्यान में रखकर एक विकल्प के रूप में अन्य मुक्त व्यापार समझौतों पर भी विचार कर सकता है। वर्तमान परिदृश्य में, भारत जब तक पीआईसी/एस की सदस्यता पर फैसला नहीं लेता है, तब तक देश को पर्यवेक्षक का दर्जा जारी रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत बौद्धिक संपदा अधिकार सहित व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं से पार पाने के लिए एक रणनीतिक समिति बनाने पर भी विचार कर सकता है। बाजार तक पहुंच बनाने के लिए परंपरागत सूचना स्रोतों पर भरोसा जताने के साथ-साथ कंपनियां स्थानीय परियोजनाओं में प्रतिभागिता करने और स्थानीय फर्मों के साथ भागीदारी करने पर भी विचार कर सकती हैं। स्थानीय आर एंड डी फर्मों के साथ भागीदारी, मंजूरी अवधि और विकास तथा मार्केटिंग लागत को कम करने के लिए एक रणनीति हो सकती है।

विनियामक अनुपालन

भारतीय फार्मासूटिकल कंपनियों को कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय मजबूत अनुपालन और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं का अनुकरण करना चाहिए। सख्त विनियामक परिवेश में अनुपालन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने से योजना, कार्यनिष्पादन और निगरानी में मदद मिल सकती है। इससे कंपनियां ऐसे महत्त्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकती हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। नियामक अपेक्षाओं के अनुसार दस्तावेजीकरण और सांख्यिकीय तकनीक जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनमें भारतीय फार्मा कंपनियों को निवेश की जरूरत है। विनियामक तंत्र में एकरूपता लाने के लिए व्यापक रिवैम्प या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940) तथा इसे लागू करने वाले विभागों का पुनर्गठन करने की जरूरत है। इससे देश में उत्पादित

नकली दवाओं की बढ़ती चिंता के समाधान में भी मदद मिल सकती है।

मूल्य और लागत दबाव

अनुकूल मूल्य पर उत्पाद का अनुमोदन लेने की संभावना बढ़ाने के लिए फार्मा कंपनियां जटिल बीमारियों के लिए ऐसी नई दवाओं के विकास या दवा वितरण तंत्र की रणनीति पर विचार कर सकती हैं जिनका मूल्य तो ज्यादा हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा कम हो। इसके अलावा, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन नई दवाओं या दवा वितरण तंत्र की प्रभावशीलता की आसानी से नकल न की जा सके।

थोक दवाएं और सामग्री

भारतीय फार्मासूटिकल उद्योग को वर्तमान में आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, आत्म निर्भरता हासिल करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए दवा सामग्री और एपीआई का प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वृद्धिशील उत्पादन करना चाहिए।

शोध एवं विकास

उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों के क्षेत्र में नवीन शोध एवं विकास अब तक उपेक्षित रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए लघु / मध्यम / लंबी अवधि की नीति की जरूरत है, ताकि निजी क्षेत्र को नई दवा के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इन क्षेत्रों में दवाओं को बाजारों तक पहुंचाने में आने वाली बाधाओं को कम किया जा सके। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को और अधिक व्यावसायोन्मुख बनाने और बाजार के लिए नवाचार लाने में सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। इसके लिए विकसित नई औषधियों के व्यावसायीकरण के लिए निजी क्षेत्र को सब्सिडी या दवा सहायता कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहन देने या इन दवाओं के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की आर एंड डी में सुधार लाने की जरूरत है।

आईपीआर

भारतीय फार्मासूटिकल उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए फार्मा कंपनियों को नई दवाओं की खोज, नवोन्मेषी डोज और मौजूदा दवाओं के नवीन प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। यह कार्य पेटेंट फाइल करने और उसके रखरखाव में आने वाली लागत में सब्सिडी देकर तथा मुकदमों और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की लागत कम करने के माध्यम से किया जा सकता है। लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) द्वारा आईपीआर गतिविधियों में अपनी प्रतिभागिता बढ़ाने और अपना महत्त्व बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी रूप से निधिक शोध संस्थानों के साथ सहयोगात्मक शोध संस्कृति विकसित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

नैदानिक शोध एवं परीक्षण

नैदानिक अनुसंधान में अनैतिक कार्य-व्यवहार और भारत में नैदानिक परीक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोटोकॉल के लिए अनुमोदन तंत्र को त्वरित एवं और अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत है। इसके अलावा, नैदानिक शोध एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाली नीति को विभिन्न स्तरों पर सहयोग देने तथा पारदर्शिता एवं खुलापन सुनिश्चित करने की जरूरत है। इन विभिन्न स्तरों में विनियम, क्षमता निर्माण, जांचकर्ताओं का प्रमाणन, नैतिकता समितियों की स्थापना, ढांचागत विकास को सहयोग, सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता पैदा करना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल हैं।

फार्मा-एसएमई विकास

फार्मा एसएमई को विदेशों में विस्तार के लिए अपनी क्षमताएं पहचानने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रयोगशालाओं तक तत्काल उनकी पहुंच बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही एसएमई क्लस्टरों को बढ़ावा देने, निरंतर प्रशिक्षण तथा ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है जिनसे विदेशों में उनके विस्तार में उन्हें मदद मिल सके।

क्लस्टर विकास

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की तरह फार्मा विशेषीकृत क्लस्टरों की स्थापना इस उद्योग के लिए विनियामक अपेक्षाओं और परिणामी लागत को पूरा करने में मददगार हो सकता है। ऐसे क्लस्टरों के लिए एक ही पेटेंट लाइब्रेरी, एक ही एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सस्ती बिजली जैसी कॉमन सुविधाएं हो सकती हैं।

कौशल विकास एवं प्रशिक्षण

फार्मासूटिकल और जीव विज्ञान उद्योग में संलग्न कर्मियों के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता, विनिर्माण और गुणवत्ता प्रबंधन, दस्तावेजीकरण कौशल, विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी कौशल, सांख्यिकीय तकनीक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रशिक्षण के लिए फार्मासूटिकल प्रशिक्षण संस्थानों का अकादमिक पाठ्यक्रम शामिल किया जा सकता है।

फॉर्म्यूलेशन मूल्य

उद्योग के अनुसार, दवा वितरण तंत्र (एनडीडीएस) और नवीन डोज़ क्षेत्रों में आर एंड डी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी मूल्य नीति अथवा बाजार आधारित मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था जारी रखी जा सकती है। यह भी सुझाव दिया गया था कि पेटेंट वाले उत्पादों के मूल्य का नियमन क्रय शक्ति के आधार पर हो।

संभावना

आईएमएस हेल्थ के अनुसार, वर्ष 2020 तक दवाओं का कुल उपयोग 2015 की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़कर 4.5 ट्रिलियन डोज तक होने की संभावना है। यह भी संभावना जताई गई है कि दवाओं के वैश्विक प्रयोग में 2020 तक होने वाली वृद्धि प्रमुख रूप से भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अफ्रीका में होगी। 2020 तक दवाओं पर वैश्विक खर्च 2015 की तुलना में 29 से 32 प्रतिशत बढ़कर 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने की संभावना है।

उद्योग सूत्रों के अनुसार, भारतीय फार्मासूटिकल उद्योग के 2015-16 से 2020-21 के दौरान 12-14 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। फॉर्म्यूलेशन और थोक दवाओं के विनियमित बाजारों में निर्यात में भी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में विनियमित बाजार भारतीय फार्मासूटिकल उत्पादों के लिए अग्रणी निर्यात स्थल बन सकते हैं। भविष्य में विनियमित बाजारों को बिना पेटेंट वाली जेनरिक दवाओं का निर्यात भी बढ़ने की संभावना है।

4 कैरिकॉम के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंध

परिचय

कैरिबियाई समुदाय (कैरिकॉम) लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में प्रमुख व्यापार क्षेत्रों में से एक है। कैरिकॉम की स्थापना चैगौरामास, त्रिनिदाद और टोबैगो संधि के जरिए हुई थी, जो 1 अगस्त, 1973 से प्रभावी हुई। इसमें 15 देश शामिल हैं - एंटीगुआ और बारबुडा, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लुसिया, सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनेडाइन्स, त्रिनिदाद और टोबैगो, बहामास, हैती और सूरीनाम। चैगौरामास संधि का नया संस्करण बनाने के लिए इसमें 1993 और 2000 के बीच संशोधन किए गए। इसे चैगौरामास संशोधित संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके जरिए कैरिकॉम सिंगल मार्केट एंड इकनॉमी (सीएसएमई) की स्थापना की गई। यह परिवर्तन जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। सीएसएमई का उद्देश्य माल एवं सेवाओं की बिक्री के ज्यादा एवं बेहतर अवसर प्रदान कर निवेश आकर्षित करते हुए इस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाना है। इसके साथ ही कैरिकॉम क्षेत्र में श्रम और पूंजी के आवागमन तथा माल तथा सेवाओं के मुक्त व्यापार को सुगम बनाना भी इसका उद्देश्य है।[1]

कैरिकॉम के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंध

कैरिकॉम देशों के साथ भारत के व्यापार में बड़ी गिरावट आई है। यह 2011 के 2890.4 मिलियन यूएस डॉलर से गिरकर 2016 में मात्र 739.9 मिलियन डॉलर रह गया। एक तरफ जहां कैरिकॉम से भारत का आयात धीरे-धीरे बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर कैरिकॉम को भारत से निर्यात में गिरावट आई है। 2011 में कैरिकॉम से आयात 229.2 मिलियन यूएस डॉलर का था, जो 2016 में बढ़कर 470.6 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। वहीं 2011 में निर्यात 2661.2 मिलियन यूएस डॉलर का था, जो 2016 में गिरकर 268.7 मिलियन यूएस डॉलर का ही रह गया। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान व्यापार संतुलन भी तेजी से गिरा, जो 2011 में 2432 मिलियन यूएस डॉलर के आधिक्य से 2016 में -201.9 मिलियन यूएस डॉलर के व्यापार घाटे में तब्दील हो गया।

कैरिकॉम देशों में त्रिनिदाद और टोबैगो भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार देश है। 2016 में कैरिकॉम को कुल निर्यात का 30.33 प्रतिशत अकेले त्रिनिदाद और टोबैगो को ही निर्यात किया गया। वहीं कैरिकॉम से कुल आयात का 32.8 प्रतिशत अकेले त्रिनिदाद और टोबैगो से ही आयात किया गया। कैरिकॉम में भारत के लिए अन्य प्रमुख निर्यात स्थलों में हैती, जमैका, बेलीज और बारबाडोस हैं। वहीं, बाहमास, गुयाना और सूरीनाम भारत के प्रमुख आयात स्रोत हैं।

भारत से कैरिकॉम को निर्यात होने वाली प्रमुख मदों में फार्मासूटिकल उत्पाद (2016 में कुल निर्यात का 21.8 प्रतिशत), रेलवे और ट्रामवे के अलावा वाहन (12.9 प्रतिशत), लौह एवं स्टील (8.8 प्रतिशत), प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान (6 प्रतिशत), कपड़ा और परिधान (4.8 प्रतिशत) और धान, आटा, स्टार्च अथवा दूध की सामग्री (4.8 प्रतिशत) शामिल रहे।

कैरिकॉम से भारत द्वारा आयात की जाने वाली मदों में प्रमुख रूप से जहाज, नावें और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर (2016 में कुल आयात का 54 प्रतिशत), खनिज ईंधन, तेल और तैल उत्पाद (29.6 प्रतिशत), लकड़ी और लकड़ी का सामान (11.3 प्रतिशत), अकार्बनिक रसायन और कीमती धातुओं का मिश्रण (2 प्रतिशत) और लौह तथा स्टील (1 प्रतिशत) शामिल रहे।

कैरिकॉम के साथ भारत के निवेश संबंध

भारत में कैरिकॉम का निवेश

अप्रैल 2000 से दिसंबर 2016 के दौरान भारत में कैरिकॉम का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 139.65 मिलियन यूएस डॉलर रहा। सेंट विन्सेंट और ग्रेनेडाइन्स कैरिकॉम क्षेत्र से सबसे बड़े निवेश स्रोत रहे, जिनका हिस्सा इस क्षेत्र से कुल एफडीआई का 40 प्रतिशत रहा। कैरिकॉम क्षेत्र से भारत में निवेश करने वाले अन्य देशों में बाहमास (28.1 प्रतिशत), सेंट किट्स और नेविस (4.9 प्रतिशत) तथा त्रिनिदाद और टोबैगो (1.8 प्रतिशत) शामिल हैं।

कैरिकॉम देशों में भारतीय निवेश

अप्रैल 1996 से नवंबर 2016 के दौरान भारत से कैरिकॉम देशों में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 191.4 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। इस क्षेत्र में भारतीय निवेश के लिए बाहमास सबसे बड़ा स्थल रहा, जहां इस क्षेत्र को कुल निवेश का 84.4 प्रतिशत अकेले ही निवेश किया गया। इसके बाद गुयाना का स्थान रहा (11.4 प्रतिशत)।

भारत-कैरिकॉम संबंध : हालिया पहलें

30 सितंबर, 2015 को न्यूयॉर्क में आयोजित दूसरी भारत-कैरिबियाई समुदाय मंत्री स्तरीय बैठक में दोनों पक्षों में भारत-कैरिकॉम द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इसके लिए क्षमता निर्माण, व्यवसाय और व्यापार संवर्द्धन, लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देना, परियोजना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि व्यवसाय आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा कारोबारी कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन और वीजा का सुगमीकरण जैसे कार्यों पर चर्चा हुई। इस संबंध में, कैरिकॉम ने क्षेत्र में व्यापार संवर्द्धन कार्यक्रम का आयोजन करने के भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया।[2]

[1] विदेश मंत्रालय, भारत सरकार कैरिबियन कम्यूनिटी एंड कॉमन मार्केट (कैरिकॉम) जनवरी 2013

[2] विदेश मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1 : कैरिकॉम देशों के साथ भारत का व्यापार (यूएस मिलियन डॉलर में)

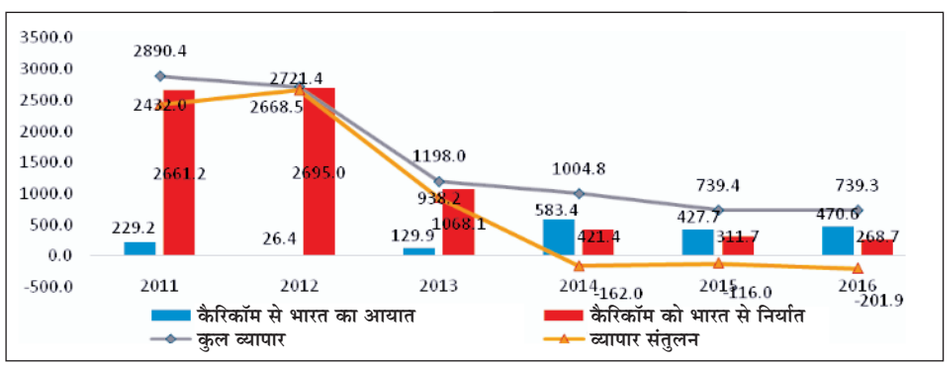

स्रोत : आईटीसी ट्रेडमैप, यूएन कॉमट्रेड

आसियान के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंध

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) भारत के लिए एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण व्यापार साझीदार है। इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कँबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनेई और थाईलैंड शामिल हैं। भारत ने 1991 में लुक ईस्ट नीति शुरू की थी और 1992 में भारत आसियान के साथ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना तथा 1996 में इसे पूर्ण डायलॉग पार्टनर का दर्जा मिला। इसके बाद आसियान भारत संबंधों को मजबूत करने तथा संवाद बढ़ाने और दोनों के लिए हितकारी विषयों पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 2013 में आसियान भारत केंद्र की स्थापना की गई। अप्रैल 2015 में भारत ने आसियन केंद्रित प्रक्रियाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से आसियान के लिए जकार्ता में अपना अलग दूतावास स्थापित किया और राजदूत की नियुक्ति की।

भारत आसियान के बीच बढ़ता व्यापार निम्नलिखित आंकड़ों में स्पष्ट देखा जा सकता है। दोनों के बीच कुल व्यापार 2004 के 16.1 बिलियन यूएस डॉलर से चार गुना बढ़कर 2016 में 64.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया और 2013 में तो यह 80.2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। चूंकि आसियान से हमारा आयात ज्यादा है और निर्यात कम, इसलिए आसियान से भारत का व्यापार घाटा रहता है। 2015 में यह व्यापार घाटा 15.1 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ गया था। हालांकि 2016 में कुछ कम होकर 11.8 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। हाल के वर्षों में भारत से आसियान को निर्यात में कमी खनिज ईंधन और तेल तथा तैल उत्पादों के निर्यात में गिरावट के कारण आई, जो 2013 के 11.1 बिलियन यूएस डॉलर से गिरकर 2016 में 4.3 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया। वहीं, कार्बनिक रसायनों का निर्यात 2012 के 2.1 बिलियन यूएस डॉलर से गिरकर 2016 में 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का ही रह गया। एनीमल और वेजिटेबल फैट और तेलों के निर्यात में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जो 2012 के 8 बिलियन यूएस डॉलर से गिरकर 2016 में 5.7 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। इसी तरह खनिज ईंधन और खनिज तेल का निर्यात भी 2012 के 10.3 बिलियन यूएस डॉलर से गिरकर 2016 में 7.7 बिलियन यूएस डॉलर का ही रह गया।

आसियान देशों में भारतीय निर्यातों के लिए सिंगापुर (27.9 प्रतिशत) सबसे बड़ा निर्यात स्थल रहा। इसके बाद वियतनाम (22.6 प्रतिशत), मलेशिया (15.9 प्रतिशत) और इंडोनेशिया (11.9 प्रतिशत) का स्थान रहा। भारत से आसियन को निर्यात में प्रमुख रूप से खनिज, तेल और उनके उत्पाद (16.4 प्रतिशत), मांस तथा मांस उत्पाद (10.1 प्रतिशत), मशीनरी और बॉइलर (6.6 प्रतिशत), जहाज, नौकाएं और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर (6 प्रतिशत), मछली और मत्स्य उत्पाद (5.8 प्रतिशत), मोती, कीमती धातुएं और रत्न (4.4 प्रतिशत), कार्बनिक रसायन (4.4 प्रतिशत) आदि शामिल हैं।

भारत ने आसियान देशों में सबसे ज्यादा 31.9 प्रतिशत इंडोनेशिया से आयात किया। इसके बाद मलेशिया (22.6 प्रतिशत), सिंगापुर (17.6 प्रतिशत), थाईलैंड (14 प्रतिशत) का स्थान रहा। भारत आसियान देशों से प्रमुख रूप से खनिज ईंधन और तेल और तैल उत्पाद (20.2 प्रतिशत), एनिमल और वेजिटेबल फैट (15 प्रतिशत), इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण और पुर्जे (11.5 प्रतिशत), कार्बनिक रसायन (4.8 प्रतिशत), प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान (4.4 प्रतिशत) का आयात करता है।

आसियान में भारत का समग्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1996 से 2016 तक 63.2 बिलियन यूएस डॉलर रहा। भारतीय एफडीआई के लिए सिंगापुर सबसे बड़ा स्थल है। इसी प्रकार, इन देशों से भारत को एफडीआई आवक अप्रैल 2000 से मार्च 2016 के बीच 47.7 बिलियन यूएस डॉलर रही, जो इस अवधि के दौरान कुल एफडीआई आवक की 16.5 प्रतिशत रही। इस तरह आसियान भारतीय बाजार में मॉरिशस (33.2 प्रतिशत) के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेशक रहा। आसियान देशों में सिंगापुर का निवेश सबसे ज्यादा है। आसियान से कुल एफडीआई आवक में से करीब 96 प्रतिशत एफडीआई आवक सिंगापुर से ही है। अन्य महत्त्वपूर्ण निवेशक इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड हैं।

आसियान के साथ भारत का सहयोग विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन में भी परिलक्षित होता है। ये परियोजनाएं कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, लोगों के बीच संवाद और कनेक्टिविटी आदि क्षेत्रों की हैं। 2011 से अब तक आसियान सचिवालय के जरिए 48.85 मिलियन यूएस डॉलर की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। फरवरी 2016 में हुई आठवीं दिल्ली वार्ता में भारत और आसियान के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई थी। यह चर्चा पारस्परिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रही। इसके अलावा कारोबार तथा मंत्री स्तरीय बैठकों के साथ अकादमिक सत्र का आयोजन भी किया गया।

वर्ष	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
आयात	8.5	10.6	16.3	21.0	26.7	24.0	29.6	40.3	42.7	42.3	44.5	41.5	38.2
निर्यात	7.6	10.3	12.4	13.8	19.4	17.9	23.0	34.5	32.3	37.9	31.3	26.4	26.4
कुल व्यापार	16.1	20.9	28.7	34.9	46.1	41.9	52.6	74.8	75.0	80.2	75.8	67.9	64.7
व्यापार घाटा	1.0	0.3	3.9	7.2	7.3	6.1	6.7	5.8	10.4	4.4	13.2	15.1	11.8

स्रोत : ट्रेड मैप, आईटीसी जेनेवा

6

ईरान के साथ व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं

भारत और ईरान की भाषा, संस्कृति और परंपराएं एक रही हैं। 1947 तक दोनों मुल्कों की सरहदें भी एक रहीं। भारत और ईरान के बीच 15 मार्च, 1950 को राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान यात्रा के दौरान दोनों मुल्कों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तेहरान घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। फिर 2003 में नई दिल्ली घोषणा के जरिए इस कार्य को और आगे बढ़ाया गया और भारत-ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी का विजन रखा गया। 22-23 मई, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बंदरगाह विकास, खनन, निर्माण और ढांचागत संरचना जैसे क्षेत्रों में 12 एमओयू / करारों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट और परिवहन पर एक त्रिपक्षीय करार पर भी हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली में 28 दिसंबर, 2015 को आयोजित भारत-ईरान संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक में व्यापार, वित्त, ऊर्जा, ढांचागत संरचना और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

ईरान के साथ भारत का व्यापार

चूंकि भारत ईरान से क्रूड ऑयल का आयात करता है इसलिए बीते कई वर्षों से भारत का ईरान के साथ व्यापार घाटा चला आ रहा है। 2011-12 में13.8 बिलियन यूएस डॉलर के आयात (जैसा कि चार्ट 1 में दिखाया गया है) के चलते उस वर्ष व्यापार घाटा सबसे ज्यादा 11.4 बिलियन यूएस डॉलर था। इसी साल दोनों देशों के बीच व्यापार भी 16.2 बिलियन यूएस डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के चलते 2011-12 के बाद से द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट आने लगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग चैनल धीरे-धीरे अप्रासंगिक हो गए। अब 2016 में आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भारत से ईरान को निर्यात बढ़ने के साथ व्यापार संबंधों में सुधार आने की उम्मीद है। अप्रैल-जनवरी (2016-17) के दौरान भारत से ईरान को 1.9 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया। वहीं, इसी अवधि के दौरान ईरान से 8.2 बिलियन यूएस डॉलर का आयात किया गया। ईरान 2016 में 30वां सबसे बड़ा निर्यात स्थल रहा, जिसे भारत द्वारा कुल वैश्विक निर्यात का 0.9 प्रतिशत निर्यात किया गया। ईरान भारत के लिए 14वां सबसे बड़ा आयातक देश रहा, जिसने भारत के वैश्विक आयात का 2.3 प्रतिशत आयात किया।

ईरान को भारत द्वारा निर्यात में चावल, चाय, लौह एवं स्टील, कार्बनिक रसायन, धातुएं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी दवाएं / फार्मासूटिकल आदि मदें शामिल हैं। भारत द्वारा ईरान से प्रमुख रूप से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद आयात किए जाते हैं, जिनका हिस्सा ईरान से कुल आयात का 71 प्रतिशत है। इसके बाद अकार्बनिक / कार्बनिक रसायनों, उर्वरकों, प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान, फल और मेवा, कांच और कांच का सामान, प्राकृतिक और सुसंस्कृत मोती, कीमती रत्न आदि का स्थान है। अप्रैल-सितंबर 2016 के दौरान चीन के बाद भारत ईरानी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा और ईरान भारत को क्रूड की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश रहा।

ईरान के साथ भारत के निवेश संबंध

अप्रैल 1996 से नवंबर 2016 के दौरान ईरान में संयुक्त उपक्रमों और पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाइयों में भारतीय एफडीआई 179.5 मिलियन यूएस डॉलर रही। एस्सार, ओवीएल, टाटा स्टील, पर्सिया रोहित माइंस एंड इंडस्ट्रीज कंपनी आदि जैसी भारतीय कंपनियों की ईरान में मौजूदगी है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का तेहरान में प्रतिनिधि कार्यालय है।

अप्रैल 2000 से दिसंबर 2016 के दौरान ईरान से भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1.0 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। भारत और ईरान के बीच संयुक्त उपक्रमों में ईरान-हिंद शिपिंग कंपनी, मद्रास फर्टिलाइजर कंपनी और चेन्नै रिफाइनरी शामिल हैं।

चाबहार बंदरगाह के लिए ईरान के साथ भारत का समझौता

2003 में भारत और ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना के निष्पादन की सहमति बनी, लेकिन पश्चिम के प्रतिबंधों के चलते कार्य में देरी हो गई। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान चाबहार पर एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। चाबहार बंदरगाह को इक्विप करने के लिए 85 मिलियन यूएस डॉलर का भारतीय निवेश भी किया जाएगा। त्रिपक्षीय ट्रांजिट करार (चाबहार करार) पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के परिवहन मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। यह बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान के जरिए रणनीतिक परिवहन और व्यापार कॉरिडोर के रूप में काम करेगा और यूरोप तथा मध्य एशिया जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक भारत की पहुंच को आसान बनाएगा। इस तरह व्यापार में समय भी बचेगा और लागत भी कम आएगी। बंदरगाह विकास और आईपीजीपीएल (इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड) तथा ईरान की आर्य बंदेर के बीच संचालन के लिए एक द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य दो टर्मिनलों का विकास करना और 10 साल तक उनका संचालन करना एवं बहुउद्देश्यीय और सामान्य क्षमताओं वाली कार्गो के साथ 5 बर्थों को संभालना है।

चार्ट 1 : बीते 10 वर्षों में ईरान के साथ भारत का व्यापार (बिलियन यूएस डॉलर)

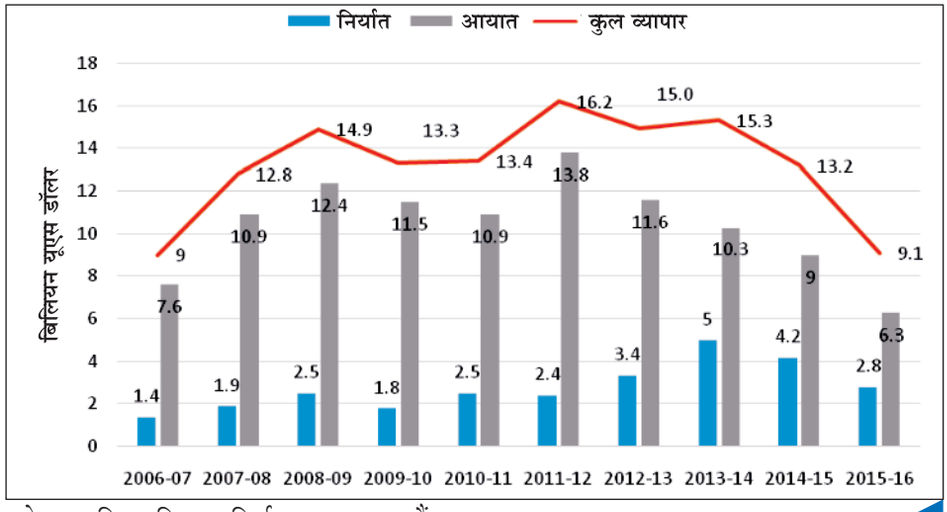

स्रोत : वाणिज्य विभाग, निर्यात-आयात डाटा बैंक

एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों पर विशेष बल के साथ भावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है। ये ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातक समुदाय को जोखिम और दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं, जो उन्हें नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने और मौजूदा विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने में मदद करती हैं। एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। बैंक अब तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप और सीआईएस क्षेत्रों के 63 देशों को 15.86 बिलियन यूएस डॉलर की 212 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कर चुका है, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

2. एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार के आदेश पर और उसके सहयोग से जुलाई-सितंबर 2016 के दौरान निम्नलिखित ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई :

[i] केन्या सरकार को 15.00 मिलियन यूएस डॉलर और 29.95 मिलियन यूएस डॉलर की दो ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की। ये ऋण-व्यवस्थाएं केन्या में क्रमशः विभिन्न लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा रिफ्ट वैली टेक्सटाइल फैक्ट्री (रिवाटेक्स ईस्ट अफ्रीका लिमिटेड) के विकास के लिए प्रदान की गई हैं। इन दोनों ऋण-व्यवस्थाओं सहित बैंक भारत सरकार के सहयोग से केन्या को अब तक 106.55 मिलियन यूएस डॉलर की तीन ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कर चुका है। इससे पहले केन्या सरकार को ऋण-व्यवस्था बिजली और ट्रांसमिशन लाइनों के लिए प्रदान की गई थी।

[ii] मलावी सरकार को लांजे स्थित लिखुबुला नदी से ब्लांटायर के बीच नई जल आपूर्ति प्रबंधन व्यवस्था के निर्माण के लिए 23.50 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। इस ऋण-व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार के सहयोग से मलावी को अब तक 180 मिलियन यूएस डॉलर की चार ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। इससे पहले मलावी को ऋण-व्यवस्थाएं सिंचाई, तंबाकू ग्रैडिंग प्लांट, कपास प्रसंस्करण, ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव, सिंचाई नेटवर्क, चीनी प्रसंस्करण उपकरण और ईंधन भंडारण सुविधा के लिए प्रदान की गई थी।

[iii] नाइजर सरकार को ठोस कचरा प्रबंधन एवं लैंडफिल परियोजना के लिए 30 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण व्यवस्था प्रदान की गई। इस ऋण-व्यवस्था सहित बैंक द्वारा भारत सरकार के सहयोग से नाइजर को अब तक 126.54 मिलियन यूएस डॉलर की पांच ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इससे पहले नाइजर को ऋण-व्यवस्थाएं बसों, ऑटोमोबाइल, आटा मिलों, मोटर पंपों, सौर विद्युतीकरण और सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, अर्द्ध शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए पेय जल आपूर्ति के लिए प्रदान की गईं।

[iv] सेनेगल गणराज्य में बसों की खरीद के लिए 26 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। इस ऋण-व्यवस्था सहित भारत सरकार के निर्देश पर एक्ज़िम बैंक की ओर से सेनेगल को अब तक कुल 288.88 मिलियन यूएस डॉलर की 13 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं बसों, सिंचाई परियोजनाओं, आईटी प्रशिक्षण परियोजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना, अस्पतालों को मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति और मत्स्य विकास परियोजनाओं के लिए दी गई हैं।

[v] सिएरा लिओन में ट्रांसमिशन लाइन तथा सबस्टेशन के लिए सिएरा लिओन सरकार को 78 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई है। उक्त ऋण-व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार के सहयोग से सिएरा लिओन सरकार को अब तक कुल 123 मिलियन यूएस डॉलर की पांच ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं सिएरा लिओन में ट्रैक्टरों की खरीद और संबंधित कार्यों, हार्वेस्टर, चावल थ्रैशर, चावल मिल, कीटाणुनाशक स्प्रे उपकरण पेयजल की आपूर्ति हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदान की गई हैं।

[vi] तंज़ानिया को 92.18 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था तंज़ानिया के द्वीप समूह ज़ांज़ीबार में जल आपूर्ति व्यवस्था के पुनरुद्धार और सुधार के लिए प्रदान की गई है। इस ऋण-व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार के सहयोग से तंज़ानिया सरकार को अब तक कुल 615.22 मिलियन यूएस डॉलर की पांच ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं ट्रैक्टरों, पंपों और उपकरणों, दार-उस-सलाम को जल आपूर्ति और लेक विक्टोरिया पाइपलाइन के टैबोरा, इगुंगा और जेगा तक विस्तार के लिए प्रदान की गई हैं।

[vii] नेपाल को 750 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। नेपाल सरकार को यह ऋण-व्यवस्था भूकंप की तबाही के बाद पुनर्वास संबंधी परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई। इस ऋण-व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार के सहयोग से नेपाल सरकार को अब तक कुल 1,650 मिलियन यूएस डॉलर की चार ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं सड़क परियोजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं, पावर ट्रांसमिशन लाइनों और हाइड्रो पावर परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई हैं।

अधिक जानकारी के लिए
कृपया संपर्क करें :

नदीम पंजेतन
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
मेकर चैंबर IV, 8वीं मंज़िल,
222 नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

टेलीफोन : (022) 22861561
फैक्स : (022) 22823394

ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

8 तिमाही गतिविधियां

एक्ज़िम बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ राज्य से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया

भारतीय एक्ज़िम बैंक तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहमति ज्ञापन पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर तथा आंध्र प्रदेश सरकार के औद्योगिक संवर्द्धन सचिव एवं आयुक्त श्री शमशेर सिंह रावत द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

एक्ज़िम बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए निर्यातकों को सहयोग प्रदान करता है। यह सेवाएं मार्केटिंग संबद्धताओं का सुगमीकरण कर आंध्र प्रदेश में तैयार किए जाने वाले उत्पादों का निर्यात बढ़ाने तथा उनके लिए सही भागीदार खोजने में मदद करेंगी। इसके अलावा, बैंक क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के आयोजन के जरिए कौशल विकास में मदद सहित चुनिंदा व्यापार मेलों व प्रदर्शनियों में निर्यातकों की सहभागिता बढ़ाने तथा शोध गतिविधियों के जरिए भी निर्यातकों को सहयोग करेगा।

एक्ज़िम बैंक विभिन्न विकसित बाजारों जैसे यूएसए, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ आदि की संस्थाओं के साथ विकसित किए गए अपने संस्थागत संबंधों का लाभ उठाकर आंध्र प्रदेश के निर्यातकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

हैदराबाद में बैंक का एक क्षेत्रीय कार्यालय है और अपनी इस उपस्थिति का लाभ उठाकर बैंक राज्य में निर्यातकों को निधिक सहायता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुचने में मदद करने के लिए इच्छुक है।

भारतीय एक्ज़िम बैंक ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को किया और मजबूत

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने निर्यात-आयात बैंकों और विकास वित्त संस्थानों के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) के लिए मुंबई में 26-30 सितंबर, 2016 तक पांच दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन किया। जी-नेक्ज़िड का गठन 2006 में अंकटाड के तत्वावधान में किया गया था और आज दुनियाभर के 25 संस्थान इसके सदस्य हैं। इस कार्यशाला का उद्घाटन एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी समन्वयक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के भारत प्रवासी प्रतिनिधि श्री यूरी अफानसीव द्वारा किया गया। दोनों वक्ताओं ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में विकास वित्त संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

इस कार्यशाला का उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को और अधिक मजबूत करना तथा आपसी अनुभवों को साझा कर कुछ नया रचना-बुनना था, जिसके लिए जी-नेक्ज़िड की आधारशिला रखी गई थी। कार्यशाला में भारतीय रिज़र्व बैंक सहित निर्यात वित्त, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों, ढांचागत विकास, ऋण बीमा, व्यापार वित्त जैसे विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष भारतीय वित्तीय संस्थानों व एक प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। पांच दिन की इस कार्यशाला में ब्राजील के विकास बैंक बीएनडीईएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ जांबिया, इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट (टोगो), इंडोनेशिया एक्ज़िम बैंक, नाईजीरियाई एक्ज़िम बैंक और सऊदी एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

एक्ज़िम बैंक ने 3.375% प्रतिवर्ष के कूपन पर 10 साल के लिए 1 बिलियन डॉलर जुटाए

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने 28 जुलाई, 2016 को सफलतापूर्वक 10 साल का 1 बिलियन यूएस डॉलर का बॉन्ड निर्गम जारी किया। यह 144/ए रेगएस फॉर्मैट में बैंक का पहला बॉन्ड है। साथ ही यह भारतीय निर्यात-आयात बैंक के लिए सबसे बड़ा और 2016 में भारत से बाहर एक बार में जारी किया गया सबसे बड़ा निर्गम है। निर्गम को 157 से ज्यादा निवेशकों से कुल 2.50 बिलियन यूएस डॉलर का अभिदान मिला, जो निर्गम के आकार से ढाई गुना ज्यादा है। शुरुआत में निर्गम 500 मिलियन डॉलर आकार का रखा गया था, लेकिन निवेशकों की जबरदस्त मांग के चलते इसे बढ़ाकर 1 बिलियन यूएस डॉलर का कर दिया गया। निर्गम से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल भारतीय परियोजना निर्यातों, विदेश में निवेश को सहयोग करने और ऋण-व्यवस्था पोर्टफोलियो में दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। शुरुआत में निर्गम को यूएस ट्रेजरी दर से 210 बेसिस पॉइंट ऊपर बेचा जाना तय हुआ था, किन्तु बाद में बैंक इस निर्गम को यूएस ट्रेजरी दर से 187.5 बेसिस पॉइंट पर लाने में कामयाब रहा। फलस्वरूप बैंक ने 3.383% की विद्यमान दर की तुलना में 3.375% की दर पर बॉन्ड जारी किए, जो मजबूत बाजार स्थितियों में निगेटिव प्रीमियम को दर्शाता है।

यह वर्ष 2000 के बाद से 500 मिलियन यूएस डॉलर के लेन-देन पर किसी भी भारतीय संस्था के नोट्स पर मिला सबसे कम प्रतिफल है। भौगोलिक दृष्टि से इसका वितरण यूएस में 61%, एशिया में 20% और यूरोप में 19% रहा। यूएस में संस्थागत निवेशकों को 61% आवंटन भारत से बाहर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के लिए सबसे ज्यादा है। निर्गम के लिए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, बार्कलेज, सिटीग्रुप, जेपी मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जॉइंट लीड मैनेजर और बुक रनर के रूप में काम किया। भारतीय एक्ज़िम बैंक को मूडीज से बीएए3 (सकारात्मक) और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स से बीबीबी- (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है, जो भारत सरकार की रेटिंग के समतुल्य है।

भारतीय फार्मासूटिकल उद्योग: चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर एक्ज़िम बैंक का शोध अध्ययन जारी

एक्ज़िम बैंक द्वारा भारतीय फार्मासूटिकल उद्योग : चुनौतियां और संभावनाएं शीर्षक से एक व्यापक शोध अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इसकी पहली प्रति नई दिल्ली में 31 अगस्त, 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग सचिव सुश्री रीता ए. तेवतिया को भेंट की गई। अध्ययन में बताया गया है कि भारतीय फार्मासूटिकल उद्योग ने वैश्विक फार्मा क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान हासिल कर लिया है। लेकिन बदलते विनियामक परिवेश और व्यापार में मंदी के कारण विभिन्न चुनौतियां भी हैं। अध्ययन में विशिष्ट रूप से कहा गया है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) करारों और ट्रांसएटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (टीटीआईपी) करारों का भारतीय फार्मा उद्योग पर गंभीर असर पड़ने वाला है और इससे भारतीय जेनरिक दवाओं का उद्योग भी प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं, फार्मासूटिकल इंस्पेक्शन को-ऑपरेशन स्कीम (पिक्स) विनियामक परिवेश भारतीय फार्मा उद्योग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) फार्मा उद्योग के लिए, क्योंकि उन्हें पिक्स की जीएमपी रूपरेखा के अनुरूप अपनी फैक्ट्रियों को अपग्रेड करने के लिए ज्यादा निवेश करना पड़ेगा।

मशीनरी सेक्टर : हालिया ट्रेंड और संभावनाएं

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मशीनरी सेक्टर का रणनीतिक महत्त्व है और यह विनिर्माण गतिविधियों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। इस सेक्टर का आर्थिक वृद्धि में गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यह विनिर्माण के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराते हुए उद्योगों के विकास को सुगम बनाने का काम करता है। इस तरह यह सेक्टर भारत में प्रमुख विनिर्माण विकास को प्रभावित करता है।

भारत में आज मशीनरी का मजबूत और विविधतापूर्ण आधार है, जो बीती सदी में आजादी के बाद से देश की आयात विकल्प नीति का नतीजा है। भारत में मशीनरी उत्पादन में महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भारत इन उत्पादों का बड़ा आयातक बना हुआ है। व्यापार घाटे को संतुलित करने और आत्म निर्भरता के लिए इस सेक्टर में घरेलू क्षमताओं का विकास करना बेहद जरूरी है।

उत्पादन परिदृश्य

पूंजीगत माल के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में (आईआईपी) (आधार वर्ष : 2004-05) में 2005-06 से 2010-11 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई और 2009-10 को छोड़ दें तो इस पूरी अवधि के दौरान यह वृद्धि दर सामान्य आईआईपी से ऊंची रही। हालांकि, 2014-15 को छोड़ दें तो 2011-12 के बाद से पूंजीगत माल सूचकांक में लगातार ऋणात्मक वृद्धि ही दर्ज की गई। 2014-15 के दौरान इंडेक्स में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई **(एक्ज़िबिट)**।

2011-12 से 2015-16 के दौरान मशीनरी और उपकरणों के लिए आईआईपी (एनआईसी 29), अकाउंटिंग और कँप्यूटिंग मशीनरी (एनआईसी 30) में ऋणात्मक से मध्यम वृद्धि दर दर्ज की गई। इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण (एनआईसी 31) में 2013-14 और 2014-15 के दौरान डबल डिजिट वृद्धि दर दर्ज की गई, जिसमें 2015-16 में 11.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

व्यापार परिदृश्य

भारत मशीनरी का निवल आयातक देश है। भारत द्वारा 2014 में 19.3 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की मशीनरी का निर्यात किया गया, जबकि 31.0 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की मशीनरी का आयात किया गया। एक तरफ जहां निर्यात में बीते कुछ वर्षों से लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर बीते दो वर्षों से आयात में भी गिरावट आ रही है। नतीजतन इन उत्पादों में व्यापार घाटा कम हुआ है, फिर भी यह 11.7 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर बना हुआ है।

2010-2014 के दौरान मशीनरी के समग्र निर्यात के साथ-साथ भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली प्रसंस्करण संयंत्र मशीनरी का निर्यात भी बढ़ा। चीन और अन्य देशों से सस्ते उपकरणों की उपलब्धता के चलते भारत में बड़े प्रसंस्करण उपकरणों का आयात बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, विकसित देशों मे नए, नवोन्मेषी और तकनीकी रूप से उन्नत प्रसंस्करण संयंत्र उपकरणों की उपलब्धता के चलते भी आयात बढ़ा है। बीते कुछ वर्षों से भारतीय वेंडर अंतरराष्ट्रीय वेंडरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नई और नवोन्मेषी तकनीकें अपना रहे हैं। इससे प्रसंस्करण संयंत्र उपकरणों के आयात में कुछ हद तक कमी आई है।[1]

2014 में अमेरिका भारतीय मशीनरी के निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार था, जिसे कुल मशीनरी निर्यात का 15 प्रतिशत निर्यात किया गया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), जर्मनी और यूके (निर्यात में प्रत्येक का हिस्सा 5 प्रतिशत) अन्य प्रमुख निर्यात स्थल रहे। हालांकि एशियाई देश (चीन को छोड़कर) शीर्ष आयातक तो नहीं हैं, लेकिन भारत के महत्त्वपूर्ण निर्यात स्थल जरूर हैं।

मशीन टूल को छोड़कर मशीनरी की सभी श्रेणियों में भारत के लिए चीन सबसे बड़ा आयात स्रोत रहा। 2014 में भारत द्वारा इस श्रेणी में किए गए कुल आयात का 31.0 बिलियन यूएस डॉलर का आयात चीन से ही किया गया, जो एक तिहाई से ज्यादा रहा। इसके बाद जर्मनी (14 प्रतिशत), संयुक्त राज्य अमेरिका (10 प्रतिशत) और जापान (9 प्रतिशत) का स्थान रहा।

संभावनाएं

उपभोक्ताओं के इस्तेमाल की चीजों के उत्पादन वाले उद्योगों की क्षमता बढ़ने और मांग में तेजी से मध्यावधि में सामान्य उद्देश्य वाली मशीनरी के उत्पदान में वृद्धि होने की संभावना है। ऑटोमोटिव मांग में सुधार आने से बियरिंग जैसे उद्योगों को फायदा होगा। रसायन और संबंधित उत्पादों, तेल और गैस जैसे तरल पदार्थों के उद्योगों की क्षमता संवर्द्धन से देश के पंप और वाल्व उद्योगों को लाभ मिलेगा। एसी, फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान (व्हाइट गुड्स) में कँप्रेसर जैसी चीजों की मांग बढ़ने से उद्योग के इस खंड में मध्यावधि के दौरान तेजी बनी रहने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट 2017-18 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। सड़कों और राजमार्गों के लिए आवंटन भी बढ़ा है। ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए सरकार ने अतिरिक्त निवेश निश्चित किया है। इन परियोजनाओं के निष्पादन से खनन और निर्माण उपकरण सेक्टर में तेजी आने के आसान हैं।

देश में बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन तथा वितरण नेटवर्क में भी काफी विस्तार होने की उम्मीद है। परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में विकास के अतिरिक्त सरकार ने 2022 तक 175 जीगा वॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार 380 अरब रुपए के निवेश से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की योजना भी बना रही है। ये सभी फैक्टर इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग के लिए बेहतर साबित होंगे।

चूंकि देश में इन उत्पादों की मांग में सुधार आना तय है, इसलिए विनिर्माओं को वैश्विक मानकों के समांतर अपने मानक बनाने और तकनीकी क्षमताओं में सुधार में निवेश के जरिए गति बनाए रखनी चाहिए।

एक्ज़िबिट : औद्योगिक उत्पादन के सामान्य और पूंजीगत माल सूचकांक में उतार-चढ़ाव

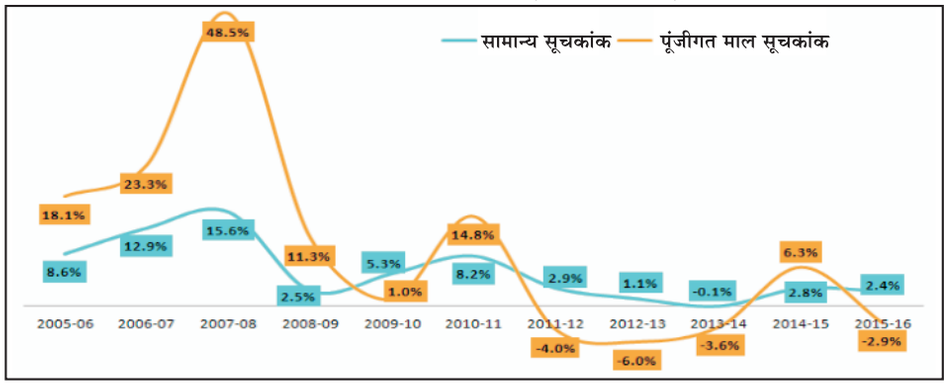

[1] टेकनेवियो

10 भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का परिदृश्य

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का नाम आते ही याद आता है ट्रांसमिटर रेडियो का ज़माना। यह 60 के दशक की बात है। दरअसल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने की सरकारी पहल के बाद विकसित हुआ। धीरे-धीरे इसका विस्तार हुआ लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनने लगी। ट्रांसमिटर रेडियो बना, कैल्कुलेटर बना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी घरों तक पहुंचा। 1980 के दशक तक आते-आते रंगीन टीवी बनने लगे और दुनिया रंगीन हो गई।

1980 का दशक इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए स्वर्णिम काल कहा जाता है। यह वह दौर था जिसमें कँप्यूटर से लेकर टेलीकॉम उत्पाद तक विकसित हुए और सूचनाओं के आदान-प्रदान में डिजिटल शब्द जुड़ा। याद कीजिए 1990 का दशक, जिसके मध्य में हर तरफ सॉफ्टवेयर का शोर था। भारत ने भी अपना ध्यान सॉफ्टवेयर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर लगा दिया। आयात शुल्क घटे और हार्डवेयर सेक्टर भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खुल गया। यह प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई जब 1997 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी करार पर हस्ताक्षर किए।

वर्तमान में, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और 2020 तक इसके 400 बिलियन यूएस डॉलर तक का हो जाने की उम्मीद है। हालांकि तब तक 104 बिलियन यूएस डॉलर का ही उत्पादन होने की संभावना है। इस तरह मांग और आपूर्ति में 296 बिलियन यूएस डॉलर का अंतर आने के आसार हैं। वर्तमान में, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बमुश्किल 5-10% का मूल्य वर्धन हो पाया है। सैमसंग, डेल और ह्यूलेट पैकर्ड जैसी कंपनियां 90% तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आयात करती हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन काफी बढ़ा है, फिर भी मांग पूरी नहीं हो पाती है और भारत को आयात करना पड़ता है।

व्यापार परिदृश्य

भारत इलेक्ट्रॉनिक सामान का शुद्ध आयातक है, जिसका व्यापार घाचा 2015 में 35.79 बिलियन यूएस डॉलर रहा था। भारत अपना ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन से आयात करता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2015 में 61.3% रहा था। इस व्यापार घाटे में चीन का सबसे बड़ा हिस्सा टेलीकॉम उपकरणों (69%) का है। इसके बाद कँप्यूटर हार्डवेयर (62%), इलेक्ट्रॉनिक कँपोनेंट (60%), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (43%) का स्थान आता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और आयात के लिए सरकारी प्रोत्साहन

1. देश की जरूरतें पूरी करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए वैश्विक स्तर का इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और विनिर्माण उद्योग बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 को अधिसूचित किया गया।
2. इस सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय सहयोग देने वाली मोडिफाइड स्पेशल इन्सेंटिव पैकेज स्कीम (एम-एसआईपीएस) शुरू की गई।
3. नवोन्मेषी माहौल बनाने तथा शोध एवं विकास के उद्देश्य से उद्योगों की भागीदारी से इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ) स्थापित की गई, जिसे निधियों की निधि कहा गया। एम-एसआईपीएस और ईडीएफ को केंद्रीय बजट में बढ़ाकर 745 करोड़ रुपए कर दिया गया।
4. सरकार ने भारत में दो वेफर फैब्रिकेशन विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
5. सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने की नीति लागू है।
6. इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्तीय सहयोग मिलता है।
7. चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सुरक्षा मानकों के अनिवार्य अनुपालन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, ताकि निम्न मानकों और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात कम किया जा सके।
8. ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिए एक उद्यमिता पार्क की स्थापना, जो आईपी निर्माण और उत्पाद विकास में सहायक होगा।
9. इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

संभावनाएं

तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आय और उच्च तकनीक वाली डिवाइसों के प्रति आकर्षण, नवोन्मेषी उत्पाद, उत्पादों की प्रतिस्पर्धी कीमतें, संगठित खुदरा क्षेत्र तथा वितरण नेटवर्क का विस्तार एवं सरकारी पहलों के चलते भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं।

निम्नलिखित के लिए घरेलू क्षमताओं के विकास और एफडीआई को प्रोत्साहन देने के लिए रणनीतियां बनाना। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा उत्पादन प्रशिक्षण केंद्रों का विकास, मोबाइल टेलीकॉम क्लस्टर की तर्ज पर अलग से क्लस्टर, उत्पाद विकास के लिए दिशा-निर्देश और मेडिकल डिवाइस श्रेणी में विनियामक परिवेश को मजबूत बनाने, अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने, सरकारी खरीद के जरिए नवोन्मेषी उत्पादोंको प्रोत्साहन, शोध एवं विकास तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भागीदारी एवं कर ढांचे को सरल बनाने से घरेलू विनिर्माण के लिए बेहतर परिवेश बनाने में मदद मिलेगी।

एक्ज़िबिट : इलेक्ट्रॉनिक सामान में भारत के व्यापार घाटे में चीन का हिस्सा (2015)

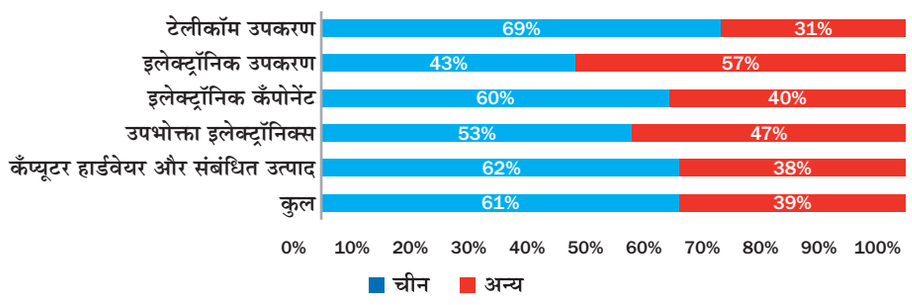

स्रोत : यूएन कॉमट्रेड

एक्ज़िम बैंक ने तमिलनाडु में महिला बुनकरों को सहयोग प्रदान किया

एक्ज़िम बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए निर्यात क्षमता के सृजन और संवर्द्धन के साथ-साथ भारतीय कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा भी बढ़ाता है। एक्ज़िम बैंक विदेशों में अवसर चिह्नित करने और भारतीय निर्यातक कंपनियों को विदेशी बाजारों में वितरकों / खरीदारों / भागीदारों की तलाश में सहयोग कर उनके वैश्वीकरण प्रयासों में भी मदद करता है। एक्ज़िम बैंक हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के दस्तकारों की क्षमता निर्माण और उनके उत्पादों को निर्यात के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उत्पाद विकास कार्यशालाओं और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उन्हें भी सहयोग प्रदान करता है।

मध्य अगस्त से मध्य नवंबर 2016 की तीन महीने की अवधि के लिए, एक्ज़िम बैंक ने तमिलनाडु की एक कंपनी को अपने बुनकरों और के कोडईकनाल के पास स्थित बुनकर इकाई के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सहयोग प्रदान किया। इस कार्यक्रम में हथकरघा के इस्तेमाल से चीजें बनाने वाली अर्द्ध-कुशल और अकुशल महिला बुनकरों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। महिला बुनकरों को साधारण हथकरघा के संचालन, सिलाई, उत्पादों की फिनिशिंग, क्वालिटी चेक और जैक्वार्ड हथकरघा चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, जो कुशल बुनकरों के लिए नई तकनीक है, क्योंकि पहले वे सिर्फ साधारण हथकरघा चलाना ही जानते थे। विभिन्न प्रकार की बुनाई तकनीकों के ज्ञान से इन बुनकरों को अपना हुनर संवारने और वैश्विक बाजार में निर्यात किए जाने योग्य उत्पाद विकसित करने में मदद मिली।

तमिलनाडु में महिला बुनकरों के लिए किए गए इस कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से ये महिलाएं आत्मनिर्भर हुईं और प्रत्येक प्रतिभागी को प्रू-लूमिंग (यार्न, वेफ्ट आदि तैयार करना) से लेकर लूम सेट करना, जैक्वार्ड बुनाई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हथकरघा पर फैब्रिक बुनना और सिलाई तथा उत्पादों की फनिशिंग तक की पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के घरेलू साज-सज्जा और दैनिक इस्तेमाल के उत्पाद तैयार किए गए।

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र गतिविधियां

जुलाई - सितंबर 2016

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र (ईसीएल) देशभर के टियर-I और टियर-II शहरों में सक्रियता से सेमिनारों का आयोजन करता रहा है। इन सेमिनारों में भारतीय निर्यात संगठन संघ (फिओ), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), कस्टम्स, ईसीजीसी और अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों के वक्ताओं ने जानकारी प्रदान की। इस तरह सेमिनारों / कार्यशालाओं ने भारत के व्यापार और निवेश के विभिन्न भागीदारों को एक मंच पर लाने में योगदान दिया और इनमें भारतीय निर्यातकों / आयातकों से जुड़े मसलों को संबोधित किया गया।

उत्तर पूर्व क्षेत्र के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न संभावनाओं, उनके उत्पादों की निर्यात क्षमताओं और क्षेत्र के निर्यातक समुदाय को वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध विभिन्न वित्तपोषण योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए ईसीएल ने भारतीय वाणिज्य संघ के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उद्यमियों को प्रोत्साहन विषय पर अगरतला में 6 सितंबर, 2016 को सेमिनार कराया।

इसी तरह, विश्व अर्थव्यवस्था और भारतीय व्यापार परिदृश्य के प्रति जागरूक करने के लिए ईसीएल ने भारतीय निर्यात संगठन संघ (फिओ) के साथ मिलकर उभरता वैश्विक व्यापार परिदृश्य - भारत के निर्यात-आयात व्यापार पर प्रभाव विषय पर 16 सितंबर, 2016 को कोलकाता में सेमिनार कराया।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

दीपाली अग्रवाल
महाप्रबंधक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.

टेलीफोन : (022) 22172829
फैक्स : (022) 22182572

ई-मेल : mas@eximbankindia.in
ecl@eximbankindia.in

पुस्तक समीक्षा

विकास सहयोग में भारत का दृष्टिकोण

प्रकाशक : राउटलेज (15 अप्रैल 2016)
मूल्य : 6,451 रुपए

विकास भागीदारी में भारत की भूमिका बीते वर्षों में काफी बदल गई है और भारत आज विकास यात्रा में प्रमुख सहयोगी की भूमिका में है। इस सहयोग के विभिन्न पहलुओं को उकेरती किताब विकास सहयोग में भारत का दृष्टिकोण (इंडियाज़ अप्रोच टू डेवलपमेंट कॉपरेशन) में विकास सहयोगमें भारत के योगदान का विश्लेषण किया गया है। किताब चार खंडों में है, जिनमें वैश्विक सहयोग परीदृश्य में भारतीय विकास सहयोग का मूल्यांकन करते हुए इसके प्रभावों पर चर्चा की गई है।

पहले खंड में भारतीय विकास सहयोग के आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। दूसरे खंड में भारतीय विकास सहयोग की समकालीन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के सहयोग पर एस. चतुर्वेदी लिखते हैं कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन विकास और दवाओं तथा वैक्सीन की आपूर्ति में सहयोग पर भारत का परंपरागत द्विपक्षीय फोकस बीते दशक में कैसे बदला है और अब द्विपक्षीय न रहकर निधियों और सहयोगपूर्ण शोध के जरिए बहुपक्षीय हो गया है। 5वें अध्याय में भारत सरकार की ऋण-व्यवस्थाओं के प्रभाव और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है।

तीसरे खंड में भारत द्वारा नेपाल, अफगानिस्तान और अफ्रीका के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में दिए गए सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें आर. बेरी का शोध अध्ययन अफ्रीका में भारतीय सहयोगमें भारत के दक्षिण-दक्षिण सहयोग को निरूपित करने वाली रणनीतियों और उपायों पर चर्चा की गई है। अंतिम खंड में भारतीय विकास सहयोग पर बाहरी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। 10वें अध्याय में एक्स. लि और टी. झोऊ दक्षिण-दक्षिण सहयोग के दो सबसे बड़े सहभागियों चीन और भारत की तुलना करते हैं। 11वें अध्ययन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी ऐसी ही तुलना की गई है।

12 देशों का सूक्ष्मावलोकन

भूटान

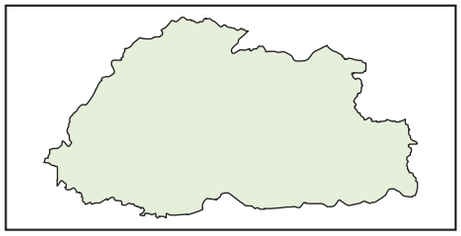

आईएमएफ के अनुसार, 2017 में भूटान सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिसकी जीडीपी वृद्धि दर लगभग 8.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। सकल सावधि निवेश में तेजी से विस्तार इस विकास दर का प्रमुख कारण है। पुनात्सांगचु-II जलविद्युत परियोजना को पूरा करने के निर्णय से निवेश बढ़ने की उम्मीद है। यह परियोजना 2018 मध्य तक शुरू होगी। 2015 में शुरू हुई दगाचु जलविद्युत परियोजना से आने वाले राजस्व के इस्तेमाल से इस साल सरकारी व्यय में वृद्धि होगी। जलविद्युत परियोजनाओं में निर्माण गतिविधियों के चलते 2017-18 में औद्योगिक आउटपुट में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। ऋण विस्तार के परिणाम के रूप में घरेलू व्यय भी बढ़ने की उम्मीद है।

रवांडा

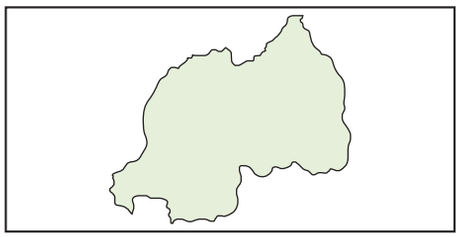

रवांडा का आर्थिक विकास ऊर्जा और टेक्सटाइल विनिर्माण क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर आधारित रहा है। चाय और कॉफी की कम कीमतों के बावजूद निवेश के चलते रवांडा के कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। यह निवेश विपरीत मौसमी परिस्थितियों से निपटने, उत्पादन बढ़ाने और वाणिज्यिक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। न्याबारोंगो नदी पर 28 मेगावाट के जलविद्युत संयंत्र के साथ लेक किवु विद्युत संयंत्र (75 मेगावाट) के दूसरे चरण से राष्ट्रीय स्तर पर बिजली आपूर्ति तथा खनन उत्पादन के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान मिलेगा। निवेश आकर्षित करने और कॉफी का मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई भूमि रजिस्ट्रेशन पहल के चलते कृषि पैदावार मध्यावधि में अच्छी रहने की उम्मीद है।

संयुक्त अरब अमीरात

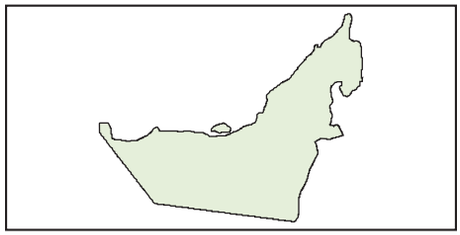

तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की विकास दर 2016 में 2.5 प्रतिशत ही रही। इससे सरकारी व्यय भी घटा और बैंकिंग तरलता भी कम हुई। इस तरह निवेश को झटका लगा। हालांकि 2016 की अंतिम तिमाही में ज्यादा तेल खनन, निवेश परियोजनाओं के पुनरुद्धार और गैर-तेल क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन से निजी क्षेत्र में वृद्धिदर्ज की गई। हालांकि ओपेक द्वारा तेल खनन में अनिवार्य कमी लाने से 2017 में आर्थिक विकास के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। यूएई 2020 में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन भी करने वाला है। इसमें बहुत से दर्शकों के आने की उम्मीद है, जिससे आने वाले वर्षों में निजी खपत और सेवाओं का निर्यात बढ़ने की उम्मीद है।

ब्राजील

ब्राजील गहरी मंदी से उभरने को तैयार है, जिसकी वास्तविक जीडीपी में 2016 में 3.8 प्रतिशत की गिरावट आई।2017 में आर्थिक नीति में समायोजन के जरिए निवेशकों का भरोसा दोबारा कायम करने और मंदी से उबरने की उम्मीद है। ब्राजील सरकार ने बड़े राजकोषीय सुधार किए हैं और कारोबार शुरू करने में लागत घटाने वाले उपाय कर रही है। हालांकि अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए सही पथ पर है, लेकिन कुछ घरेलू जोखिम भी हैं। लंबी अवधि में ब्राजील के विकास में जनसांख्यिकी की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि काम करने वाली आबादी कम होगी। 2017 में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा (13 प्रतिशत) बनी रहने के आसार हैं। निम्न ब्याज दरों से घरेलू और कॉर्पोरेट ऋण बढ़ने की उम्मीद जरूर है, लेकिन ऋण वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) कमजोर ही रहने के आसार हैं। कच्चा माल तैयार करने वाले उद्योग बाहरी मांग के चलते बढ़ेंगे, लेकिन चीन की धीमी वृद्धि दर के कारण इनकी गति भी मंद ही रहने के आसार हैं।

फिलीपींस

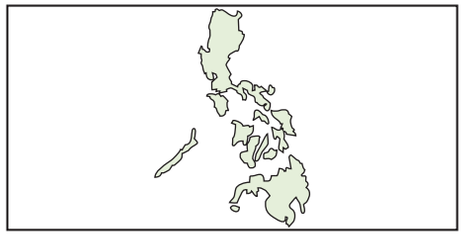

वैश्विक मंदी के दौरान फिलीपींस रेमिटैंस के तीव्र प्रवाह और अपनी अच्छी निजी खपत के चलते अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में स्थिर रहा है। 2016 में इसकी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रही। 2017 में यह वृद्धि दर उच्च आधार प्रभावों के चलते निवेश के कुछ मंदा पड़ने से 6.4 प्रतिशत तक रहने के आसार हैं। जुलाई-सितंबर 2016 तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी। 2017 में निजी खपत में तेजी जारी रहेगी, जिससे महंगाई दर मध्यम रहने और औपचारिक रोजगार बढ़ने और रेमिटैंस का प्रवाह अच्छा बने रहने की उम्मीद है। सरकार द्वारा कई ढांचागत परियोजनाओं में तेजी लाने से सार्वजनिक निवेश भी मजबूत रहने की उम्मीद है। चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी के चलते बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) सेक्टर के तुलनात्मक रूप से पृथक रहने की उम्मीद है, क्योंकि इसके मजबूत आधारभूत सिद्धांत अस्थिर ऋण वृद्धि की अनुमति नहीं देते। फलस्वरूप 2017 में फिलिपींस का मर्केंडाइज और सेवाओं का निर्यात 5.7 प्रतिशत की स्थिर दर से बढ़ने की उम्मीद है।

ब्रिटिश पाउंड

इस साल ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर की तुलना में अब तक 10 प्रतिशत गिर चुका है। यह तीन दशक से ज्यादा समय में सबसे बुरी स्थिति है। इस साल अब तक हुआ अधिकांश नुकसान उस दिन हुआ जब लोगों ने यूरोपीय संघ (ईयू) से ब्रिटेन का 43 साल पुराना रिश्ता खत्म करने का निर्णय लिया। इस आश्चर्यजनक कदम के परिणामस्वरूप ब्रिटिश पाउंड 1985 के बाद सबसे निचले स्तर पर गिर गया।

ब्रेक्ज़िट नाम के इस ऐतिहासिक जनमत के बावजूद यूके यूरोपीय संघ का हिस्सा रहेगा, क्योंकि एक बार अनुच्छेद 50 के अमल में आने के बाद इस प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम दो साल लगेंगे या ज्यादा भी लग सकते हैं। इस आर्थिक ब्लॉक से बाहर निकलने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए इसे लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत एक आधिकारिक नोटिस देना होगा। यूरोपीय संघ से जाने की प्रक्रिया का नियमन लिस्बन संधि द्वारा ही होता है और बाहर जाने की शर्तों पर वार्ता / सहमति के लिए दो साल का समय होता है। इसके लिए जनमत के तुरंत बाद नोटिस नहीं दिया गया था, क्योंकि इस प्रस्ताव को संसद द्वारा पारित होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संकेत दिए हैं कि यह प्रक्रिया 2016 के अंत से पहले शुरू नहीं हो पाएगी। हालांकि यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि ब्रिटेन अनुच्छेद 50 के अंतर्गत यह प्रक्रिया शुरू करेगा या दूसरा जनमत संग्रह कराएगा या इसकी सदस्यता की शर्तों पर दोबारा वार्ता करेगा। इससे यूरोपीय संघ के साथ यूके के बदले रिश्तों में लंबे समय तक अनिश्चितता रहने के आसार हैं।

सिंगापुर डॉलर

सिंगापुर डॉलर (एसजीडी) सिंगापुर की आधिकारिक मुद्रा है। सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा सिंगापुर डॉलर की ऐतिहासिक परिवर्तनशीलता को बनाए रखा गया है।

सिंगापुर की अर्थव्यवस्था इस साल (2016) की दूसरी तिमाही में बढ़त बनाने में कामयाब रही। दूसरी तिमाही में वृद्धि दर पहली तिमाही की तुलना में 0.2 प्रतिशत ज्यादा रही। इसके अतिरिक्त 2016 की पहली तिमाही की वृद्धि दर भी वर्ष दर वर्ष आधार पर 2.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही, जो पिछले प्रिंट के 1.8 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर से ज्यादा रही। 2016 की पहली छमाही में वृद्धि दर 2.0 प्रतिशत को देखते हुए 1-3 प्रतिशत का आधिकारिक वृद्धि दर अनुमान के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है।

2016 की दूसरी तिमाही में अच्छी वृद्धि दर और तकनीकी मंदी की संभावना न के बराबर होने के बावजूद इस शेष वर्ष में वृद्धि दर में गिरावट का जोखिम बना हुआ है। साल की दूसरी छमाही में यदि वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक परिस्थितियां स्थिर नहोकर और बिगड़ीं तो मुद्रा अवस्फीति को संभालने के लिए ब्याज दरें कम करने का विकल्प अब भी खुला है। ध्यान देने वाली बात यह है पड़ोसी देशों में आधार दरों में हुई कटौती को देखते हुए वैश्विक मौद्रिक नीति और कटौती की ओर बढ़ सकती है।

यूएस डॉलर

बीते कुछ हफ्तों से यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा अगले हफ्ते दस साल में दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ाने के कयास लगाए जाते रहे हैं। हालांकि कम से कम बाजार के परिप्रेक्ष्य से तो इसकी संभावना कम ही है, फिर भी प्रमुख फेड वक्ताओं और जारी हुए प्रमुख यूएस आर्थिक डाटा ने इस चर्चा को दूसरी ओर मोड़ दिया है। परिणामस्वरूप वित्तीय बाजार पर इसका असर होता है और बाजार में भी अनिश्चितता बढ़ती है।

इसके अतिरिक्त, सितंबर में अब तक यूएस आर्थिक डाटा में सामान्य गिरावट दर्ज की गई, जो रोजगार (एनएफपी) के संबंध में आशंका से भी ज्यादा रही और विनिर्माण तथा सेवा उद्योग (पीएमआई) दोनों ने सितंबर में दरें बढ़ने की संभावना को और कम कर दिया। हाल ही में जारी हुआयूएस आर्थिक डाटा में आशंका से भी ज्यादा बुरी स्थिति रही, जो पहले से अस्थिर फेड द्वारा यूएस दरें बढ़ाने पर विराम लगाता है। विशेष रूप से, खुदरा बिक्री, कोर खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन में आशंका से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

फेड के दोहरे मैंडेट पर इसकी अस्थिरता के अलावा और भी बहुत सी चिंताएं हैं जो फेड को सितंबर में ब्याज दरें बढ़ाने से रोक सकती हैं। ऐसी ही सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है - यूएस अर्थव्यवस्था लंबी अवधि के ढांचागत मसलों से गुजर रही है, जो इसकी लंबी अवधि की विकास दर में बाधा बन सकते हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने बूढ़ी होती जनसांख्यिकी, वृहद आर्थिक संकट की स्थिति के लिए बचत की युगचेतना, मजबूत डॉलर और गिरती उत्पादकता वृद्धि का जिक्र करते हुए इन मसलों पर चर्चा की और आशंका जताई कि इन कारणों के चलते 2016-2017 के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत भी शायद ही रह पाए।

14 माइग्रेशन और भारत में रेमिटैंस

एक्ज़िम बैंक ने भारतीय नागरिकों द्वारा भारत या विदेशों में विश्वविद्यालयों एवं अकादमिक संस्थानों में अंतराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1989 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार की स्थापना की थी। पुरस्कार स्वरूप तीन लाख पचास हजार रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 2015 का एक्ज़िम बैंक ईरा पुरस्कार डॉ. चिन्मय तुंबे को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारत में प्रवासन और रेमिटैंसः ऐतिहासिक, क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक आयाम शीर्षक के शोध प्रबंध के लिए दिया गया। यह लेख डॉ. चिन्मय तुंबे के पुरस्कार प्राप्त शोध प्रबंध पर आधारित एक्ज़िम बैंक के कार्यकारी आलेख से लिया गया है।

माल और सेवाओं की आवाजाही की तुलना में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन की परिघटना पर शोधकर्ताओं का ध्यान प्रायः कम ही जाता है। अंतराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में प्रवासन के बजाय माल एवं सेवाओं की आवाजाही पर शोध की प्रधानता है। इस परिदृश्य में, अर्थपूर्ण आंकड़ों और शोध के अभाव में भारत जैसे विकासशील देशों में क्षेत्रीय प्रवासन की गुत्थी को सुलझाना और भी जटिल हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में शोध करना और भी महत्त्वपूर्ण और दिलचस्प हो जाता है। भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर पाया गया है कि भारत की लगभग 20 प्रतिशत आबादी को कवर करने वाले क्षेत्रों में पूरी 20वीं सदी के दौरान प्रवासन की दर ज्यादा रही है। यह प्रवासन निरंतर, पुरुष प्रधान, रेमिटैंस आधारित रहा है। प्रवासन गहन जिलों में 1881 से आज तक लिंगानुपात के आंकड़े जुटाते समय यह देखा गया कि उच्च प्रवासन दर वाले क्षेत्रों में महिलाओं का लिंगानुपात पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा, जैसे - रत्नागिरी, उडुपी आदि। वहीं, जिन जिलों में ज्यादा प्रवासी आए वहां लिंगानुपात कम रहा, जैसे - मुंबई, दिल्ली आदि। यह आम धारणा है कि क्षेत्रों का अल्प आर्थिक विकास प्रवासन को बढ़ावा देता है, लेकिन ऐसा ही हो, यह आवश्यक रूप से सही नहीं है। कम से कम आंकड़े तो इस धारणा की पुष्टि नहीं करते। अल्प विकास और प्रवासन के बीच संबंध ज्यादा देर तक टिका नहीं रहता, क्योंकि अल्पविकसित और विकसित दोनों क्षेत्रों के लोगों को बेहतर अवसरों के लिए प्रवासन का रास्ता अपनाना ही पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो मेजबान क्षेत्रों से अपने स्वयं के नेटवर्क के जरिए प्रवासी समूहों का अध्ययन प्रवासन को समझने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेमिटैंस पर ज्यादा निर्भर रहने वाले क्षेत्रों का आर्थिक मॉडल रेमिटैंस आय पर निर्भर होता है। रेमिटैंस आधारित अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि औद्योगीकरण का स्तर कम रहने के बावजूद रेमिटैंस मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) उच्च है। इस तरह यह शोध अध्ययन इस धारणा को भी एक तरह से तोड़ता है कि रेमिटैंस पर उच्च निर्भर अर्थव्यवस्थाएं अवांछनीय हैं।

आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत की रेमिटैंस अर्थव्यवस्था घरेलू / अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों रेमिटैंस के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत वैश्विक रूप से सबसे बड़ा रेमिटैंस प्राप्तकर्ता देश और दूसरा सबसे बड़ा घरेलू रेमिटैंस बाजार है। 2007-08 में कुल अंतरराष्ट्रीय रेमिटैंस 10 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा रहा। केरल, पंजाब और गोवा जैसे राज्य अंतरराष्ट्रीय रेमिटैंस बाजार में सबसे बड़ी रेमिटैंस आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं। वहीं, बिहार, यूपी और राजस्थान घरेलू रेमिटैंस बाजार में रेमिटैंस निर्भर तीन शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं। 1991 में उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रेमिटैंस बाजार दोनों में रेमिटैंस का ट्रेंड बढ़ा है। घरेलू रेमिटैंस का 50 प्रतिशत शीर्ष 25 प्रतिशत परिवारों को मिलता है और स्रोत क्षेत्र की असमानता बढ़ती है। दिलचस्प है कि 60 प्रतिशत घरेलू लेन-देन अंतरराज्यीय होते हैं और 70 प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमों के जरिए होता है (संयोग है कि चीन के लिए यह आंकड़ा 25 प्रतिशत है)। इस तरह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रवासी कामगारों के वित्तीय समावेशन की बड़ी संभावना बनती है।

रेमिटैंस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़त लगातार जारी है। इसकी गति 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों से 2008 तक तेज रही। इसका मेजबान और गृह देशों की आर्थिक स्थितियों से कोई संबंध नहीं है।लेकिन 2008 के वित्तीय संकट के बाद रेमिटैंस में करीब दो दशक बाद 2009 में पहली बार गिरावट आई और वह भी 6 प्रतिशत की। इस संदर्भ में, यह देखा जाना दिलचस्प है कि रेमिटैंस चक्र मेजबान देश के व्यवसाय चक्र से जुड़ा है या नहीं। कोई कह सकता है कि मेजबान देश की आर्थिक स्थितियों में रेमिटैंस प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। विषम और विविधतापूर्ण प्रवासन स्थल वाले देशों के व्यवसाय चक्र के उतार-चढ़ाव का कम प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत जैसे देश, जहां वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भी रेमिटैंस के प्रवाह में स्थिरता बनी रही। इसका कारण यह है कि भारत में रेमिटैंस इसके प्रवासी कामगारों से आता है, जो खाड़ी से लेकर अमेरिकी देशों तक फैले हुए हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपनी उच्च विकास दर के चलते निवेशकों को विदेशोंमें मूल्यवान निवेश अवसर प्रदान करती हैं। इसलिए व्यवसाय चक्र और गृह देश के रेमिटैंस चक्र में एक सकारात्मक सह संबंध देखा गया है। इस तरह, दुनिया के सबसे बड़े रेमिटैंस प्राप्तकर्ता देशों में से एक भारत के अपनी इसी स्थिति में बने रहने की उम्मीद है।

संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यूएस डॉलर)	**1365.4**	**1708.5**	**1823.0**	**1829.0**	**1863.2**	**2042.4**	**2072.3[f]**	**2217.7[f]**
प्रति व्यक्ति जीडीपी (यूएस डॉलर)	**1146.7**	**1411.7**	**1482.1**	**1462.9**	**1466.4**	**1581.1**	**1581.4[f]**	**-**
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	**8.6**	**8.9**	**6.7**	**5.6****	**6.6****	**7.2****	**7.6[P]****	**7.1 (अप्रैल-जून)[e]****
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.8	8.6	5.0	1.5**	4.2**	-0.2**	1.2[P]**	1.8 (अप्रैल-जून)[e]**
उद्योग	9.2	7.6	7.8	3.6**	5.0**	5.9**	7.4[P]**	6.0 (अप्रैल-जून)[e]**
सेवाएं	10.5	9.7	6.6	8.1**	7.8**	10.3**	8.9[P]**	9.6 (अप्रैल-जून)[e]**
जीडीपी में क्षेत्रगत हिस्सा (%)								
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	14.6	14.6	18.5	17.8**	17.5**	16.3**	15.3[P]**	13.7 (अप्रैल-जून)[e]**
उद्योग	28.3	27.9	32.5	31.9**	31.5**	31.2**	31.2[P]**	31.7 (अप्रैल-जून)[e]**
सेवाएं	57.1	57.5	49.0	50.3**	51.0**	52.5**	53.5[P]**	54.6 (अप्रैल-जून)[e]**
जनसंख्या (एमएन)	**1190.7**	**1210.2**	**1230.0**	**1250.2**	**1270.6**	**1291.4**	**1312.6[f]**	**-**
मुद्रास्फीति दर (सीपीआई, वार्षिक औसत %)	12.2	10.4	8.3	10.2	9.5	5.9	4.9	4.31 (सितंबर '16)
मुद्रास्फीति दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	3.8	9.6	8.9	7.4	6.0	2.0	-2.5	3.57 (सितंबर '16)
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	**6.5**	**4.8**	**5.9**	**4.9**	**4.5**	**4.1**	**3.9[e]**	**3.5[e]**
विनिमय दर (रु. / यूएस डॉलर, औसत)	47.4	45.6	47.9	54.4	60.5	61.1	65.5	66.66 (सितंबर 30,'16)
विनिमय दर (रु. / यूरो, औसत)	67.1	60.2	65.9	70.1	81.2	77.5	72.3	74.75 (सितंबर 30,'16)
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**178.8**	**249.8**	**306.0**	**300.4**	**314.4**	**310.3**	**262.0**	**131.4 (अप्रैल-सितंबर '16)**
% परिवर्तन	*-3.5*	*39.8*	*22.5*	*-1.8*	*4.7*	*-1.3*	*-15.6*	*-1.7^*
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**28.2**	**36.4**	**56.7**	**60.9**	**63.2**	**56.7**	**30.4**	**14.1 (अप्रैल-सितंबर '16)**
% परिवर्तन	*2.3*	*29.0*	*55.9*	*7.3*	*3.8*	*-10.2*	*-46.4*	*-16.9^*
गैर-तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**150.6**	**213.4**	**249.2**	**239.5**	**251.2**	**253.6**	**231.6**	**117.3 (अप्रैल-सितंबर '16)**
% परिवर्तन	*-4.6*	*41.8*	*16.8*	*-3.9*	*4.9*	*0.9*	*-8.7*	*-0.5^*
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**288.4**	**369.8**	**489.3**	**490.7**	**450.2**	**448.0**	**380.4**	**174.4 (अप्रैल-सितंबर '16)**
% परिवर्तन	*-5.1*	*28.2*	*32.3*	*0.3*	*-8.3*	*-0.5*	*-15.1*	*-13.8^*
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**87.1**	**106.0**	**155.0**	**164.0**	**164.8**	**138.3**	**82.9**	**39.3 (अप्रैल-सितंबर '16)**
% परिवर्तन	*-7.0*	*21.6*	*46.2*	*5.9*	*0.4*	*-16.0*	*-40.1*	*-18.6*
गैर-तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**201.2**	**263.8**	**334.3**	**326.7**	**285.4**	**309.7**	**297.5**	**135.1 (अप्रैल-सितंबर '16)**
% परिवर्तन	*-4.2*	*31.1*	*26.7*	*-2.3*	*-12.6*	*8.5*	*-3.9*	*-12.3^*
व्यापार संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)	**-109.6**	**-120.0**	**-183.3**	**-190.3**	**-135.8**	**-137.7**	**-118.4**	**-43.0 (अप्रैल-सितंबर '16)**
सेवा निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)***	**96.0**	**124.6**	**140.9**	**145.7**	**151.8**	**158.1**	**154.3**	**65.8 (अप्रैल-सितंबर '16)**
*सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)****	49.7	53.1	62.2	65.9	69.4	73.1	74.2	18.2 (अप्रैल-जून '16)
सेवा आयात (बिलियन यूएस डॉलर)***	**60.0**	**80.6**	**76.9**	**80.8**	**78.7**	**81.6**	**84.6**	**39.0 (अप्रैल-अगस्त '16)**
सेवा संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)***	36.0	44.0	64.0	64.9	73.1	76.5	69.7	**26.9 (अप्रैल-अगस्त '16)**
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	**-38.4**	**-47.9**	**-78.2**	**-87.8**	**-32.4**	**-26.8**	**-22.1**	**-0.3 (अप्रैल-जून)**
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष (%)	*-2.8*	*-2.8*	*-4.2*	*-4.8*	*-1.7*	*-1.3*	*-1.1*	*-0.1(अप्रैल-जून)*
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	**279.1**	**304.8**	**294.4**	**292.0**	**304.2**	**341.6**	**360.2**	**372.0 (सितंबर 30,'16)**
विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	**260.9**	**317.9**	**360.8**	**409.4**	**446.2**	**475.0**	**485.6**	**479.7 (अप्रैल-जून)**
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	18.2	18.2	21.1	22.4	23.8	23.8	23.7	23.4 (अप्रैल-जून)
अल्पावधि ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	52.3	65.0	78.2	96.7	91.7	85.5	83.4	82.1 (अप्रैल-जून)
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	20.1	20.4	21.7	23.6	20.5	18.0	17.2	17.1 (अप्रैल-जून)
कुल ऋण सेवा अनुपात (%)	5.8	4.4	6.0	5.9	5.9	7.6	8.8	7.5 (अप्रैल-जून)
एफडीआई (बिलियन यूएस डॉलर)	**37.7**	**36.0**	**46.6**	**34.3**	**36.0**	**45.1**	**55.6**	**22.8 (अप्रैल-अगस्त '16)**
जीडीआर / एडीआर (बिलियन यूएस डॉलर)	3.3	2.0	0.6	0.2	0.02	1.3	0.4	-
एफआईआई (नेट) (बिलियन यूएस डॉलर)	29.0	29.4	16.8	27.6	5.0	40.9	-4.0	5.0 (अप्रैल-अगस्त '16)
एफडीआई जावक (बिलियन यूएस डॉलर)	**15.1**	**17.2**	**10.9**	**7.1**	**9.2**	**4.0**	**8.9**	**2.3 (अप्रैल-अगस्त '16)**
मेमो आयटम्स :	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016[f]**	**2017[f]**
वैश्विक जीडीपी (% परिवर्तन)	**5.4**	**4.2**	**3.5**	**3.3**	**3.4**	**3.2**	**3.1**	**3.4**
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	3.1	1.7	1.2	1.2	1.9	2.1	1.6	1.8
उभरते हुए और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	7.4	6.3	5.3	4.9	4.6	4.0	4.2	4.6
विश्व व्यापार (वॉल्यूम, % परिवर्तन)	**14.3**	**6.9**	**2.5**	**3.2**	**3.2**	**2.4**	**2.3**	**3.8**
विश्व व्यापार निर्यात (यूएस डॉलर टर्न)	**14.9**	**17.9**	**18.0**	**18.5**	**18.6**	**16.2**	**15.9**	**16.9**
विश्व व्यापार के मूल्य में वृद्धि निर्यात (%)	**20.7**	**20.2**	**0.8**	**2.4**	**0.6**	**-13.0**	**-1.4**	**6.3**

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न मुदे; केंद्रीय बजट, आरबीआई मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट और साप्ताहिक सांख्यिकी अनुपूरक; वित्त मंत्रालय; सीएसओ; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ); विश्व आर्थिक मंच, आईएमएफ.

नोट : पी - ईएसी, भारत सरकार के अस्थायी अनुमान; ई - भारत सरकार के अनुमान; एफ - आईआईएफ अनुमान; * - 2009-10 के बाद के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान मैनुअल के आईएमएफ शेष राशि में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर बीओपी आंकड़ों के मानक प्रस्तुतीकरण के नए स्वरूप के अनुसार दिए गए हैं; ** - संशोधित आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार डेटा; # - बजट 2016-17 अनुमान.

व्यापार एवं भागीदारी अवसर

व्यापार अवसर

पैराफिन वैक्स

पेट्रोलियम उत्पादों और पैराफिन मोम के उत्पादन में संलग्न सार्वजनिक क्षेत्र की एक तेल कंपनी। भारत में कंपनी की सबसे बड़ी मोम उत्पादक इकाई है, जो मोमबत्ती बनाने में इस्तेमाल होने वाला पैराफिन मोम बनाती है।

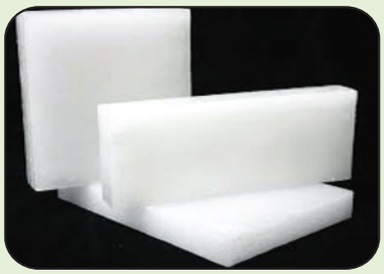

कृषि पण्य

किसानों और प्रसंस्करण कर्ताओं से सीधे जुड़ी व्यापार कंपनी, जिसकी आईएसओ 9001:2000 प्रमाणित विनिर्माण इकाई है। कंपनी बाजरा, मसाले, मसाला पाउडर, इंस्टैंट मिक्स और फ्लेक जैसे विभिन्न कृषि उत्पाद बनाती है।

फार्मासूटिकल

एलोपैथिक, न्यूट्रैसूटिकल, आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक और पशु चिकित्सा संबंधी ब्रांडेड और जेनरिक उत्पादों के विनिर्माण में संलग्न कंपनी। कंपनी 6 माह से 3 साल तक के बच्चों के लिएसिरप (पीने की दवा के रूप में) मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी बनाती है।

स्टेनलैस स्टील कॉइल

भारत के सबसे बड़े स्टेनलैस स्टील विनिर्माताओं में से एक और दुनिया के शीर्ष 10 स्टेनलैस स्टील विनिर्माताओं में शामिल। कंपनी 200, 300, 400 और डुपलेक्स ग्रेड में स्टेनलैस स्टील बनाती है।

हवा से पानी बनाने वाली मशीन

जल प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी कंपनी, जो हवा से 25 लीटर से 5000 लीटर तक पीने योग्य साफ पानी बनाने वाली अनूठी मशीनें बनाती है।

रबड़ प्रसंस्करण मशीनरी

आईएसओ 9001:2000 प्रमाणित कंपनी जो प्राथमिक रूप से टायर विनिर्माण और डिजाइन तथा इंजीनियरिंग जैसी सेवाओं, शोध एवं विकास, फैब्रिकेशन और असेंबल करने के लिए ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रदान करती है।

भागीदारी अवसर

परियोजना अवसर

(I) कोलंबिया स्थित एक कंपनी भारत से पर्यावरण संबंधी सॉल्यूशन प्रदाताओं से भागीदारी करने की इच्छुक है।

(II) जिम्बाब्वे में एक आतिथ्य-सत्कार करने वाली (हॉस्पिटैलिटी) कंपनी विक्टोरिया फाल्स के पास एक पर्यटन लॉज के निर्माण के लिए भागीदारों की तलाश में है।

निर्यात अवसर

(I) आइवरी कोस्ट, अफ्रीका की एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स काउंसिल (पीसीपीसी) ग्रेड के अनुसार हैंड सैनिटाइजर विनिर्माताओं की तलाश में है।

(II) कनाडा स्थित एक आयातक भारतीय सार्वजनिक सुरक्षा गारमेंट विनिर्माता कंपनियों की तलाश में है, जो कनाडा के लिए पैंट-शर्ट सहित यूनिफॉर्म की आवश्यकताएं पूरी कर सके।

(III) मिस्र स्थित आयातक भारत से स्टेनलैस स्टील कॉइल की थोक में खरीद करने का इच्छुक है।

इच्छुक पार्टियां निम्नलिखित संपर्क विवरणपर मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं समूह से संपर्क कर सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 2217 2600 एक्सटेंशन : 2707 / 2737; फैक्स : 2218 8268. ईमेल : maseximbankindia.in